



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 327]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

जांच शुरूआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों पर निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 15/4/2009-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27.01.2005 की अधिसूचना सं. 14/24/2003-डीजीएडी के तहत प्रकाशित हुए थे, दिनांक 13.04.2005 की अधिसूचना सं. 35/2005-सीमाशुल्क के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । मूल जांच के दौरान मै0 श्रीकृष्ण पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली आवेदक घरेलू उद्योग थे ।

2. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क)5 के अनुसार यदि पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना

आवश्यक है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं.-2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

3. विचाराधीन उत्पाद

निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में यथाउल्लिखित के समान अर्थात् थर्मल सेंसेटिव पेपर (टीएसपी) है। थर्मल सेंसेटिव पेपर बेस पेपर को थर्मल सेंसेटिव गुणधर्म प्रदान करने के लिए रसायनों के विशेष मिश्रण से कोटेड पेपर होता है। पेपर पर नियंत्रित थर्मल ताप का प्रयोग करके पेपर पर इम्प्रेशन बनाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किरणों की संवेदनशीलता के जरिए संदेशों एवं रिपोर्टों को रिकॉर्ड करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, वहाँ थर्मल सेंसेटिव पेपर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु संदेश की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। टीएसपी का प्रयोग मुख्य रूप से फैक्स मशीनों में होता है। इसका प्रयोग ईसीजी मशीनों तथा सिस्मोग्राफिक मशीन, एयरलाइन बैगेज टैगिंग, टिकट, बोर्डिंग कार्ड आदि जैसे अन्य उपकरणों में भी किया जाता है। इस उत्पाद के लिए कोई अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। तथापि मूल जाँच में इसे शुल्क के अधिरोपण हेतु उप-शीर्ष 480910, 481190, तथा 481620 के तहत वर्गीकृत किया गया था।

तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

I) इस जाँच से यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है :-

- i. समीक्षा में दिनांक 27.01.2005 की अधिसूचना सं. 14/2/2003-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जाँच में शामिल देश इंडोनेशिया, मलेशिया और यूएई हैं।
- ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी।
- iii. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

I) सूचना प्रस्तुत करना:

घरेलू उद्योग द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए पाटन एवं क्षति अथवा दोनों के

जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, कमरा सं. 240,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकती है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाली किसी पार्टी द्वारा, दूसरी पार्टियों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

III. समय सीमा :

घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पार्टियों, जिनके पते उपलब्ध होंगे, को लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी ताकि वह इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच सके। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी, जिसका पता उपलब्ध नहीं हो, भी घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

IV. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION**

New Delhi, 27th October, 2009

Initiation**(Sunset Review)**

Subject : Initiation of Sunset Review Anti-Dumping Investigation concerning imports of Thermal Sensitive Paper originating in and exported from Indonesia, Malaysia and UAE.

F. No. 15/4/2009-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 (as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Thermal Sensitive Paper (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE (hereinafter referred to as subject countries). The Final Findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/24/2003-DGAD, dated 27.1.2005. On the basis of the final findings, definitive anti dumping duties were imposed by the Central Government, on the subject goods imported from the subject countries, vide Customs Notification No.35/2005 dated 13.4.2005. M/s Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd, New Delhi was the applicant Domestic Industry during the original investigation.

2. Initiation of Sunset Review

WHEREAS in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory, therefore, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Product under Consideration

Product under consideration in the sunset review is same as was described in the original investigation i.e. Thermal Sensitive Paper (TSP). Thermal Sensitive Paper is a paper coated with a special mix of chemicals for providing thermal sensitive properties to the base paper. Impression on the paper is created by virtue of controlled thermal heat exposed on the paper. Thermal Sensitive Paper is primarily used for recording messages for electronic equipments where the machines are used to record messages and reports through sensitivity of heat rays. TSP is primarily used in fax machines. It is also used in ECG machines and other

equipments such as Seismographic machines, Airlines baggage tagging, tickets, boarding card etc. The product does not have a dedicated Customs Classification. However, during the original investigation it was covered under sub-heading 480910, 481190 and 481620 for imposition of duty. The Customs Classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

6. Procedure

I) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both:-

- i. The review will cover all aspects of Notification No. 14/2/2003-DGAD dated 27.1.2005. The countries involved in this review investigation are Indonesia, Malaysia and UAE .
- ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st July 2008 to 30th June 2009. The injury investigation period will however cover the periods, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.
- iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

II) Submission of Information:

The Domestic industry is required to submit information on prescribed *pro forma* (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty **within forty days (40 days)** of the date of issue of this notification.

The exporters in subject country, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan , New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

3873 91/09-2

III) Time Limit:

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from the date of application from Domestic industry. For this purpose non confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

IV) Inspection of Public File:

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority